



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

मई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11, 1975 (पौष 21, 1896)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 1975 (PAUSA 21, 1896)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned Gazzettes of India Extraordinary were published up to the 28th February 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

— एन्ड —
— Nil —

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से बस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazzettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazzettes.
401GI/74

चिप्पी-सूची

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 7	भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य भेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	पृष्ठ 77
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी प्रफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	23	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	5
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—	भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	101
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	37	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	19
भाग II—खंड 1—प्रधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रबंध समितियों की रिपोर्ट	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	801
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य भेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	—	भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	5
पूरक संख्या 2— 21 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	19	पूरक संख्या 2— 30 नवम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बढ़ी बीमारियों से हुई मृत्यु संबंधी प्रांकडे	37

CONTENTS

PAGE	PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PART II—SECTION 3.—Sub. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	PAGE
7	PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	77
23	PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5
37	PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	101
—	PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	19
—	PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	—
—	PART II—SECTION 3.—Sub. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	801
—	SUPPLEMENT NO. 2	—	5
—	Weekly Epidemiological Reports for week ending 21st December 1974	—	29
—	Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 30th November, 1974	—	37

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम व्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1974

सं० 10(2)-बी० ओ०-111/74—वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) को 23 जून, 1973 को अधिसूचना सं० 10(4) बी० ओ० 111/73 के मिलभिले में, सरकार सहर्प, एक-व्यक्ति समिति (बैंकिंग विधि समिति) के कार्यकाल को दिसम्बर, 1975 के अंत तक और बढ़ाती है।

द० म० सुकर्णनकर,
निदेशक।

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1974

सं० 4(1)/73—केन्द्रीय सरकार आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक (अथवा उनके नामित व्यक्ति) को, आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, अमर्वाई के स्थान पर सान्ताकुज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोर्ड के एक सदस्य के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के (भूतपूर्व) विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० 16(2)/73-टी० ई० फ० दिनांक 20-1-1973 में और आगे निम्नोक्त संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में, अमाक (9) के सामने दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नोक्त प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी; अर्थात्—
“आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक (अथवा उनके नामित व्यक्ति), नई दिल्ली”।

यू० आर० कुलेंकर,
उप निदेशक।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 1974

संकल्प

सं० फी III-1 (30)/74—यह आवश्यक है कि सरकारी खारीद करने वाले सगठनों को अनावश्यक देरी किये बिना और कार्य कुशलता तथा मित्रव्ययता का सम्यक ध्यान रखते हुए सरकार की आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए।

अब खरीद किये जाने वाले सामान की निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा, मूल्य, विविधता और पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या भारत और विदेश में सामान की खरीद के लिए अपनाई गई पद्धति की दृष्टि से वर्तमान सगठन प्र्याप्ति है? इस प्रश्न पर गहराई से विचार करने, इस प्रकार के कार्यों के लिए वर्तमान सगठनों को सरल और कारबर बनाने, उनकी सरचना, कार्य और प्रक्रिया की पद्धति की दृष्टि से सरकार ने समिति गठित करने का निश्चय किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1. मंत्री पूर्ति और पुनर्वास	अध्यक्ष
2. सचिव—पूर्ति विभाग	सदस्य
3. श्री ए० एन० हक्सर	
4. श्री एम० बी० कामथ	
5. श्री एन० एम० बागले	
6. वित्त मंत्रालय (व्यव विभाग)	सदस्य
7. सचार मंत्रालय (डाक-तार बोर्ड)	सदस्य
8. रेल मंत्रालय	सदस्य
9. रक्षा मंत्रालय और	सदस्य
10. आद्योगिक विकास मंत्रालय दोनों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. योजना आयोग (राज्य सरकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए)	सदस्य
12. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और	सदस्य
13. महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान) में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि	सदस्य सचिव

विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे—

(क) सामान की अधिप्राप्ति में कार्यकुलशता और मित्रव्ययता लाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा और केन्द्रीय सरकार की ओर से की गई खरीद के लिए वित्तीय भुगतान की प्रणाली और कार्यविधि में एकल्पना लाना और सुधार के सुझाव देना।

(ख) बचत करने के लिए विलम्बता में कमी करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा और केन्द्रीय सरकार की ओर से की गई खरीद के लिए वित्तीय भुगतान की प्रणाली और कार्यविधि की जांच करना और सुधार के लिए सुझाव देना।

(ग) कोई अन्य सबंध विषय जैसे विशिष्टियां, निरीक्षण, परीक्षण, निकासी, नौभरण आदि।

(ष) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) के लिए संगठनात्मक व्यवस्था करना।

इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और वह अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के पूर्ति विभाग को यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा।

आदेश

प्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया जाये।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 1st December 1974

No. 118-Pres/74.—The President is pleased to direct that, with immediate effect, the following amendments shall be made in the rules governing the award of the President's Police & Fire Services Medal and the Police Medal published in Part I, Section I of the Gazette of India of 10th March 1951, under Notification No. 4 Pres/51, dated the 1st March 1951 as amended from time to time:—

PRESIDENT'S POLICE & FIRE SERVICES MEDAL

(1) For the existing Rule (5), substitute the following:—

"(5) When awarded for gallantry, the medal shall carry a monetary allowance at the rates and subject to the conditions set forth below. The charges thereof shall be borne by the revenues of the State/Union Territories concerned in respect of recipients belonging to the State/Union Territories and by the respective Central Police/Security Organisations in respect of officers belonging to these organisations.

- (a) Where an officer who has already been awarded either the King's Police and Fire Services Medal, or that Medal and a Bar, or Bars thereto for gallantry, is subsequently awarded the President's Police and Fire Services Medal for a further act of gallantry, he shall be paid a monetary allowance attached to the Bar to the latter Medal in addition to the original allowance and not the full allowance attached to the Medal itself. Where an officer who has already been awarded the Indian Police Medal for gallantry is subsequently awarded the President's Police and Fire Services Medal for a further act of gallantry he shall be paid the full allowance attached to the latter Medal in addition to the original allowance;
- (b) The allowance shall be granted from the date of the act for which the award is given, and, unless it is forfeited for misconduct, shall continue until death;
- (c) Where a recipient is in receipt of the allowance at the time of his death, it shall be continued for life or till re-marriage of his widow (the first married wife having the preference). In the case of a posthumous award of the Medal or a Bar, the allowance shall be paid, from the date of the act for which the award is made, to the widow (the first married wife having preference) for her life or till re-marriage;
- (d) All the recipients of this gallantry award shall be entitled to the monetary allowance on a uniform rate, irrespective of their ranks. The rates of monetary allowance for the Medal shall be Rupees sixty per mensem and for the Bar to the Medal it shall be Rupees thirty per mensem."

POLICE MEDAL

(2) For the existing sub-rule (a) of Rule (5), substitute the following:—

"(a) When awarded for gallantry the Medal shall, subject to the conditions set forth for the President's Police and Fire Services Medal for gallantry, carry a monetary allowance on a uniform rate of Rupees forty per mensem and the Bar Rupees twenty per mensem, irrespective of the rank of the

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों; मंत्रिमंडल सचिवालय; प्रधानमंत्री का सचिवालय; राष्ट्रपति के सचिव; योजना आयोग; नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक; लंदन और वाशिंगटन में भारत पूर्ति मिशनों; समिति के सदस्य सचिव, राज्य सरकारों; संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधितों को भेजी जायें।

एच० के० कोचर,
संयुक्त सचिव

recipient. The charges thereof shall be borne by the revenues of the State/Union Territories concerned in respect of the recipients belonging to the State/Union Territories and by the concerned Central Police/Security Organisations in respect of the recipients belonging to these Organisations."

A. MITRA, Secy. to the President

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF BANKING

New Delhi-110001, the 18th December 1974

No. 10(2)-B.O.PI/74.—In continuation of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Banking) Notification No. 10(4)-B.O.III/73, dated the 23rd June, 1973 Government are pleased to extend further the tenure of the One-man Committee (Banking Laws Committee) till the end of December, 1975.

D. M. SUKTHANKAR, Director

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPTT. OF EXPORT PRODUCTION)

New Delhi, the 19th December 1974

No. 4(1)/73.—The Central Government hereby appoints the Chief Controller of Imports and Exports (or his nominee), as a member of the Santa Cruz Export Processing Zone Board vice Joint Chief Controller Imports and Exports, Bombay, and makes the following further amendment in Govt. of India (formerly) Ministry of Foreign Trade, Notification No. 16(2)/73 TA EP dated the 20-1-1973. In the said Notification, for the entry against S. No. (9), the following entry shall be substituted, namely,

"Chief Controller of Imports and Exports, (or his nominee) New Delhi".

U. R. KURLEKAR, Dy. Director

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(DEPARTMENT OF SUPPLY)

New Delhi, the 24th December 1974

RESOLUTION

No. PIII-1(30)/74.—It is essential that organisations for Government purchases should be able to secure the requirements of Government without undue delay and with due regard to efficiency and economy. In view of the evergrowing volume, value, variety and complexity of stores which have to be purchased now, it has become increasingly important to consider whether the existing organisations for and the methods adopted in purchasing stores in India and abroad are adequate. With a view to examine the question in depth and make specific recommendations for streamlining the existing organisations for such functions, their structure method of work and procedures, the Government has decided to set up a Committee consisting of the following:—

Chairman

1. Minister of Supply & Rehabilitation

Member

2. Secretary, Deptt. of Supply

Non-official Members

3. Shri A. N. Haksar

4. Shri M. V. Kamath

5. Shri N. M. Wagle

Members

6. A representative each of the Ministries of Finance
(Deptt. of Expenditure)

7. Communications (P&T Board)

8. Railways

9. Defence; and

10. Industrial Development

A representative each of

11. Planning Commission (to represent the interests of
State Governments)

12. Comptroller & Auditor General; and

Member-Secretary

13. Director General (Supplies & Disposals)

The following will be the terms of reference :

(a) To identify and suggest improvements in the system
and procedures of purchases (both indigenous andimport(s) adopted by different Ministries/Departments
of the Central Government with a view to achieve the
aim of efficiency and economy in procurement.

- (b) To examine and suggest improvements in the system
and procedures of financial payments for the purchases
by and on behalf of Central Government with a view
to cut down delays to effect savings.
- (c) Any other related matters such as specifications, ins-
pection, testing, clearance, shipment etc.
- (d) Organizational set up for (a) (b) and (c) above.

The Committee will have its headquarters in New Delhi
and will submit its report to the Government of India in the
Department of Supply as early as possible.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette
of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated
to all Ministries/Departments of Government of India; the
Cabinet Secretariat; the Prime Minister's Secretariat; Secretary
to the President; the Planning Commission; the Comptroller
and Auditor General; the India Supply Missions in London
and Washington; Member-Secretary of the Committee; State
Governments; Administration of Union Territories and all
other concerned.

H. K. KOCHER, Jr. Secy.

